**प्रेस विज्ञप्ति**

**20.11.2025**

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), हैदराबाद आंचलिक कार्यालय ने फर्जी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और पैसा कमाने वाले फर्जी मोबाइल एप्लिकेशन और वेबसाइटों के माध्यम से बड़े पैमाने पर साइबर धोखाधड़ी की चल रही जांच के संबंध में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत कॉइनडीसीएक्स और कुछ क्रिप्टो वॉलेट सहित **92 बैंक खातों** में फैली **8.46 करोड़ रुपये** की राशि को अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया है।

ईडी ने अज्ञात साइबर धोखेबाजों के खिलाफ कडप्पा पुलिस द्वारा आईपीसी की धारा 420, 1860 और आईटी अधिनियम की धारा 66-सी और 66-डी के तहत दर्ज कई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। जांच में देश भर में दर्ज कई अन्य एफआईआर का खुलासा हुआ, जिनमें एनबीसी ऐप, पावर बैंक ऐप, एचपीजेड टोकन, आरसीसी ऐप, मेकिंग ऐप और कई अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सहित भ्रामक अंशकालिक नौकरी योजनाओं और धोखाधड़ी वाले निवेश अनुप्रयोगों के माध्यम से इसी तरह के व्यापक घोटाले का खुलासा हुआ।

ईडी की जाँच से पता चला है कि घोटालेबाज़ व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप्स और बल्क एसएमएस कैंपेन के ज़रिए भोले-भाले लोगों को निशाना बनाते थे और उन्हें ज़्यादा कमीशन और तुरंत मुनाफ़े का लालच देते थे। पीड़ितों को निवेश या ई-कॉमर्स से कमाई का वादा करने वाले फ़र्ज़ी ऐप्स या लिंक्स पर रजिस्टर करने के लिए राज़ी किया जाता था। उन्हें फ़र्ज़ी ई-कॉमर्स वेबसाइट्स पर सामान खरीदने या बेचने जैसे आसान काम करने को कहा जाता था, जिसके बाद रिवॉर्ड पॉइंट्स या कमाई उनके ऑनलाइन वॉलेट में दिखाई देती थी। हालाँकि, किसी भी गतिविधि में शामिल होने से पहले, पीड़ितों को अपने ऐप वॉलेट में पैसे जमा करने होते थे, आमतौर पर यूपीआई पेमेंट के ज़रिए बैंक खातों या वीपीए आईडी के ज़रिए, जो फर्जी संस्थाओं से जुड़े होते थे और व्हाट्सएप एजेंटों द्वारा साझा किए जाते थे। निवेशकों का विश्वास हासिल करने के लिए, धोखेबाज़ शुरुआत में उनके बैंक खातों में छोटे-छोटे मुनाफ़े या कमीशन जमा करते थे, और उन्हें ज़्यादा रिटर्न के लिए ज़्यादा रकम जमा करने के लिए प्रोत्साहित करते थे। एक बार बड़ी रकम जमा हो जाने के बाद, पीड़ितों द्वारा पैसे निकालने के प्रयास लगातार विफल होते थे।

जब पीड़ितों ने हेल्पलाइन नंबरों या व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर सहायता एजेंटों से संपर्क किया, तो उन्हें झूठा बताया गया कि करों या अन्य नियामक मंज़ूरियों के लिए अतिरिक्त भुगतान करना होगा। ऐसे भुगतान करने के बाद भी, निकासी असफल रही। अंततः, ऐप्स क्रैश हो गए, वेबसाइटें बंद हो गईं, उपयोगकर्ता खाते निष्क्रिय कर दिए गए और ग्राहक सहायता गायब हो गई। पीड़ितों को ज़्यादा कमीशन का लालच देकर नए सदस्य बनाने के लिए भी कहा गया, जिससे घोटाले का नेटवर्क और फैल गया।

इस योजना के ज़रिए अर्जित 285 करोड़ रुपये की आपराधिक आय 30 से ज़्यादा प्राथमिक बैंक खातों में जमा की गई, जिनका इस्तेमाल सिर्फ़ 1 से 15 दिनों की छोटी अवधि के लिए किया गया, और फिर बैंकों और क़ानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा पकड़े जाने या खाता फ़्रीज़ होने के जोखिम को कम करने के लिए 80 से ज़्यादा अन्य बैंक खातों में तुरंत ट्रांसफ़र कर दिया गया। अपराध से प्राप्त आय का एक बड़ा हिस्सा क्रिप्टोकरेंसी में बदल दिया गया या भारत में हवाला चैनलों के ज़रिए वितरित किया गया।

मनी ट्रेल विश्लेषण से पता चला है कि घोटालेबाजों ने अपराध की कमाई से प्राप्त तृतीय-पक्ष भुगतानों का उपयोग करके, बाइनेंस पर पीयर-टू-पीयर (पी टू पी) लेनदेन के माध्यम से अक्सर यूएसडीटी (टीथर) खरीदे। उन्होंने क्रिप्टो एक्सचेंजों के बीच मूल्य अंतर का फायदा उठाया और जाँच से पता चला कि वजीरएक्स, बाइहेटके और कॉइनडीसीएक्स पर विक्रेताओं ने कम दरों पर यूएसडीटी खरीदा और इसे बाइनेंस पी टू पी पर थोड़ी अधिक कीमतों पर घोटालेबाजों को बेच दिया, और अपराध की कमाई से तृतीय-पक्ष हस्तांतरण स्वीकार किए। जाँच से यह भी पता चला कि घोटालेबाजों ने गैर-KYC-अनुपालन वाले उपयोगकर्ता खातों और असत्यापित तृतीय-पक्ष भुगतानों का उपयोग करके कॉइनडीसीएक्स के माध्यम से 4.81 करोड़ रुपये मूल्य के यूएसडीटी को परिवर्तित किया।

आगे की जाँच जारी है।